

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 24/18 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :- 2018/00058

उनवान

1. मान सिंह पुत्र रूप सिंह
 2. जगदीश पुत्र रूप सिंह
 3. संजय कुमार पुत्र मान सिंह
- } जातियान जाट निवासीयान ग्राम कुरका तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरलाल पुत्र कन्हैया
2. रूप सिंह पुत्र हीरा सिंह (मृतक)
2/1. अशोक कुमारी पत्नी रूप सिंह जाति जाट निवासी बसैया कलों तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2/2. वर्षा कुमार उम्र 15 साल पुत्री रूप सिंह } नाबालिगान बली सरंक्षक माता खुद अशोक
2/3. लवली कुमार उम्र 10 साल पुत्र रूप सिंह } कुमारी पत्नी रूप सिंह जाति जाट निवासी
2/4. खैमकरण उम्र 12 साल पुत्र रूप सिंह } बसैया कलों तह0 नदबई जिला भरतपुर।
2/5. हेमन्त कुमार उम्र 8 साल पुत्र रूप सिंह }
3. भीम सिंह पुत्र निरोती } जाति जाट निवासी बसैया कलों तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. जय सिंह पुत्र निरोती }
5. बाबूलाल } पिसरान रेवती कौम खाती जांगिड ब्राह्मण निवासी वसैया कलों तहसील नदबई
6. पूरन } जिला भरतपुर।
7. पन्ना }
8. रामखिलाडी }
9. सरपंच ग्राम पंचायत गगवाना तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. उप पंजीयक महोदय तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. प्रबन्धक महोदय, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बांसी खुर्द तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैसपो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0
1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई दिनांक 16.02.2018 उनवानी चन्दा देवी
बनाम हरलाल मु0न0 153/10

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषणमाया :-

1. अदालत अगोलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. अदालत रैस्यो श्री चन्द्रनोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 09.11.2023

1. यह अदालत अंतर्गत धारा 223 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 16.02.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया चन्दा देवी ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादी/रैस्यो इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके प्रान बर्तया कलों तहसील नदबई वादिया एवं प्रतिवादी/रैस्यो के पूर्वजों की पैत्रिक आराजी है, जो वादिया एवं प्रतिवादी/रैस्यो को जरिये विसासतन अपने पूर्वजों से प्राप्त हुयो है। प्रतिवादी/रैस्यो आये दिन अपनी इच्छापूर्ति करने के लिये पैत्रिक आराजी को खुरद-बुर्द करने पर आनावा रहता है। विवादित आराजी प्रतिवादी रैस्यो संख्या 01 के नाम कर्ता खान दान होने की वजह से उनके नाम दर्ज अनिलेख है। जिसका लाम सवाल हुये विवादित आराजी में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी रैस्यो संख्या 02 को सन् 2000 से पूर्व ही विक्रय कर दिया। जबकि वादिया का विवादित आराजी में निष्क हिस्सा हरलाल पुत्र कन्हैया के साथ में निहित है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् वादिया की मृत्यु होने पर उनके वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई खारिज करते हुये, अगोलाधीन आदेश से दावा वादिया खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अगोलागट ने यह अगोल इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अदालत प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्योडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को लक्ष्य किया गया। बहत् समयपस सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अगोलांट ने-अदालत नौनो के तथ्यों को दौहरते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अगोलाधीन आदेश खिल्लाक कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। यह है कि प्रकरण में चन्दा देवी की ओर से संजय कुमार पुत्र नाम सिंह को मुख्यास्ताना दिनांक 17.10.2011 को नियुक्त कर रखा था। तत्पश्चात् चन्दा देवी की मृत्यु दिनांक 16.09.2016 को हो गयी। चन्दा देवी की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान अगोलागट एवं तीन पुत्रिया की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 के तहत दिनांक 01.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना जाकर, प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 जा0दी0 को खारिज करते हुये, दावा भी खारिज कर दिया, जो पूर्णतया कानून एवं पत्रावली के विरुद्ध है। क्योंकि सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना आवश्यक था कि चन्दा देवी की मृत्यु दिनांक 16.09.2016 को होने के बाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 अन्दर अवधि 90 दिवस प्रस्तुत किया गया है या नहीं। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र तहरीरी

तपस करीव प्रमिशरी
डागुर (पत्र)

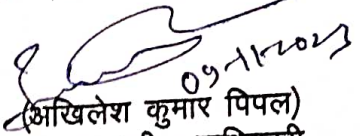
दिनांक ०१.१२.२०१६ को प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का अंकन दिनांक ०७.१२.२०१६ किया गया है। यहाँ यह भी मान लिया जावे कि प्रार्थना पत्र दिनांक ०७.१२.२०१६ को प्रस्तुत किया गया है तो भी प्रार्थना पत्र मृत्यु की दिनांक १६.०९.२०१६ से अन्दर अवधि ९० दिवस प्रस्तुत किया गया है। ९० दिवस दिनांक ०९.१२.२०१६ को होते हैं। मुताबिक कानून मियाद अधिनियम तृतीय भाग एप्लीकेशन के पार्ट-१ अनुच्छेद १२० के मुताबिक समय अवधि ९० दिवस होती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रार्थना पत्र ६० दिवस के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है जो कि कतई गलत है। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि ९० दिवस के प्रस्तुत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को चन्दा देवी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिये था। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो० ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। चन्दा देवी की मृत्यु होने के १५ दिवस बाद ही न्यायालय में मृत्यु होने की सूचना दे दी गयी थी। चन्दा देवी की मृत्यु के पश्चात् मुख्यानामा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश २२ नियम ३ मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है एवं मियाद को क्षमा करने हेतु कोई उचित कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में चन्दा देवी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश २२ नियम ३ जा०दी० दिनांक ०१.१२.२०१६ को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की प्रस्तुतीकरण दिनांक ०७.१२.२०१६ अंकित है। विधिअनुसार किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने के बाद, उसके विधिक वारिसान को ९० दिवस के अन्दर, कायम मुकाम कार्यवाही करनी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में चन्दा देवी की मृत्यु दिनांक १६.०९.२०१६ को हुयी। दिनांक १६.०९.२०१६ से अन्दर अवधि ९० दिवस, दिनांक ०९.१२.२०१६ को होते हैं। इस प्रकार प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक ०१.१२.२०१६ को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद ही प्रस्तुत किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कायम मुकाम कार्यवाही की अवधि ६० दिवस मानकर, प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। कायम मुकाम कार्यवाही की अवधि ६० दिवस ना होकर ९० दिवस होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।
6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक १६.०२.२०१८ अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह मृतक चन्दा देवी के विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक ०४.१२.२०२३ को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।



26
राज्य अपीलाण्ट प्राधिकारी
मेरठपुर (उ.प्र.)

7. निर्णय आज दिनांक 09.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्य अपील प्राधिकारी
भरतपुर

